भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 715

**दिनांक 07 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**आईएमईसी गलियारा**

**715. श्री अरविंद सावंत:**

क्या **वाणिज्य और** उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नए आईएमईसी गलियारा (भारत मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा) में हमारे देश का हिस्सा कितना है;

(ख) हमारे देश द्वारा इस गलियारे हेतु निवेश की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस गलियारे से हमारे देश को होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस गलियारे से हमारे देश को कितना लाभ/मुनाफा अपेक्षित है;

(ङ) क्या इजरायल-हमास के बीच चल रहे युद्ध के कारण इस गलियारे के प्रभावित होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने इस गलियारे के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के बारे में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

(क) से (घ) जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के अवसर पर, भारत, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिनांक 9 सितंबर 2023 को एक नया भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) विकसित करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताते हुए एक समझौता ज्ञापन की घोषणा की।

आईएमईसी का उद्देश्य भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच अपने विभिन्न आयामों में अवसंरचना विकास और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए अधिक निवेश का उपयोग करना है। आईएमईसी में दो अलग-अलग गलियारे शामिल हैं, पूर्वी गलियारा भारत को अरब खाड़ी से जोड़ता है और उत्तरी गलियारा अरब खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है। इसमें एक रेलवे मार्ग शामिल है, जो पूरा होने पर, मौजूदा समुद्री और सड़क परिवहन मार्गों के पूरक के लिए एक विश्वसनीय और किफायती सीमा पार जहाज-से-रेल ट्रांजिट नेटवर्क प्रदान करेगा – जिससे भारत, संयुक्त अरब

अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजरायल और यूरोप के बीच माल और सेवाओं की आवाजाही सक्षम होगी।

आईएमईसी से एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाकर और आर्थिक एकीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलने की आशा है। प्रस्तावित रेलवे मार्ग के पूरा होने पर, मौजूदा समुद्री और सड़क-परिवहन मार्गों के पूरक के लिए एक विश्वसनीय और किफायती सीमा पार जहाज-से-रेल ट्रांजिट नेटवर्क प्रदान किए जाने की संभावना है, जिससे भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच माल और सेवाओं का तेजी से आवाजाही सक्षम हो सके। रेलवे मार्ग के साथ-साथ इसका उद्देश्य बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए केबल बिछाने और स्वच्छ हाइड्रोजन निर्यात के लिए एक पाइपलाइन को सक्षम करना है। यह गलियारा क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करेगा, व्यापार पहुंच बढ़ाएगा, व्यापार सुविधा में सुधार करेगा, और पर्यावरणीय, सामाजिक और सरकारी प्रभावों पर बढ़ते जोर का समर्थन करेगा, गलियारा क्षमता बढ़ाएगा, लागत कम करेगा, आर्थिक एकता बढ़ाएगा, रोजगार पैदा करेगा, और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करेगा - जिसके परिणामस्वरूप एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व का परिवर्तनकारी एकीकरण होगा।

(ड.) से (च) सरकार वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखती है और आईएमईसी पहल के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न आईएमईसी भागीदार एक-दूसरे से परामर्श कर रहे हैं।